

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकल पीठ बिक्री-कर संशोधन/संदर्भ संख्या 13/2019

नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, खातीपुरा रोड, जयपुर

----अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त, कर-अपवंचन रोधी राजस्थान-1, जयपुर

----प्रत्यर्थी

के साथ

एस.बी. बिक्री-कर संशोधन/संदर्भ संख्या 8/2019 संबद्ध

नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, खातीपुरा रोड जयपुर

----अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त कर-अपवंचन रोधी, राजस्थान-1 जयपुर

----प्रत्यर्थी

एस.बी. बिक्री-कर संशोधन/संदर्भ सं. 11/2019

नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, खातीपुरा रोड जयपुर

---- अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त कर-अपवंचन रोधी , राजस्थान-1 जयपुर

---- प्रत्यर्थी

एस.बी. बिक्री-कर संशोधन/संदर्भ संख्या 15/2019

नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, खातीपुरा रोड, जयपुर

---- अपीलार्थी

बनाम

अपीलार्थी की ओर से : श्री अनंत कासलीवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री वैभव कासलीवाल के साथ
प्रत्यार्थी की ओर से : श्री पुनीत सिंघवी के लिए
श्री आयुष सिंह

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

रिपोर्टेबल

आदेश आरक्षित करने की तारीख - 08/08/2023

उच्चारित करने की तारीख - 27/09/2023

1. राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 84 (संक्षेप में "आरवीएटी अधिनियम") के तहत दायर वर्तमान बिक्री-कर संशोधन/संदर्भ (संक्षेप में "एसटीआर") को कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर स्वीकार किए गए थे:

"i) क्या इयूटी पात्रता पास बुक (संक्षेप में डीईपीबी)/इयूटी फ्री लाइसेंस/इयूटी क्रेडिट स्क्रिप की खरीद के लिए भुगतान किए गए कर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (संक्षेप में "आईटीसी") के दावे को अस्वीकार किया जा सकता है, भले ही स्क्रिप्स का उपयोग राजस्थान राज्य के भीतर तैयार माल के निर्माण के उद्देश्य से किया गया हो?

ii) "क्या ब्याज लगाया जा सकता है और वसूला जा सकता है, भले ही रिटर्न के अनुसार अधिनियम के तहत डीलर ने बकाया कर की पूरी राशि जमा की गई हो और इस तरह, पुर्नमूल्यांकन पर निर्धारित अंतर कर पर ब्याज वैध और कानूनी रूप से लगाया जा सकता है?"

2. चूंकि इन सभी एसटीआर में सामान्य मुद्दा शामिल है, इसलिए पार्टियों की सहमति से, उन्हें एक साथ सुना गया और अब इस सामान्य आदेश निर्णित किया जा रहा है। एसटीआर नंबर 13/2019 को तथ्यों को पढ़ने के लिए मुख्य फाइल के रूप में लिया जाता है।

3. इन एसटीआर के लिए संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी-निर्धारिती मोटर वाहन, औद्योगिक और रेलवे उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बेयरिंग का निर्माता है। कर अपवंचन रोधी प्राधिकारियों ने दिनांक 23.08.2016 को अपीलार्थी के व्यावसायिक परिसरों का सर्वेक्षण किया और पाया कि अपीलार्थी ने राज्य के भीतर डीईपीबी/इयूटी फ्री लाइसेंस/इयूटी क्रेडिट स्क्रिप खरीदा है और इन अमूर्त वस्तुओं की खरीद पर भुगतान किए गए कर के आईटीसी का दावा किया है और उसका लाभ उठाया है। जांच अधिकारी ने पाया कि यदि इन वस्तुओं का निपटान आरवीएटी अधिनियम की धारा 18 के अनुसार नहीं किया जाता है तो इन वस्तुओं पर कोई आईटीसी उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, कर-चोरी का एक मामला बनाया गया था और इसे अधिनिर्णयन/आकलन अधिकारी (संक्षेप में "एओ") को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिन्होंने अपीलार्थी-करदाता को सुनवाई का अवसर देने के बाद उनके द्वारा लिए गए इनपुट क्रेडिट को अस्वीकार कर दिया और देय कर जमा न करने पर ब्याज लगाया। एओ ने यह भी माना कि अपीलार्थी-करदाता ने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है और कर की चोरी का कारण बना है, और इसलिए आरवीएटी अधिनियम की धारा 61 (2) (ख) के तहत जुर्माना लगाया है। मूल्यांकन आदेश से असंतुष्ट होने के कारण, अपीलार्थी-निर्धारिती ने अपीलार्थीय प्राधिकरण के समक्ष अपील की, जिसने 16.08.2017 के आदेश के तहत आईटीसी के उलट और ब्याज और जुर्माना लगाने की पुष्टि की और अपील को खारिज कर दिया। अपीलार्थीय आदेशों के खिलाफ, अपीलार्थी-करदाता ने राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष आरवीएटी अधिनियम की धारा 83 के तहत अपील की, जिसने 13.09.2018 के अपने आदेश के तहत आईटीसी और ब्याज लगाने को वापस लेने की पुष्टि की, लेकिन जुर्माना रद्द कर दिया।

4. अपीलार्थी-करदाता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने पंजीकृत डीलर से डीईपीबी/इयूटी फ्री लाइसेंस/इयूटी क्रेडिट स्क्रिप खरीदा था जिसका उपयोग मशीनरी/कच्चे माल के आयात के लिए किया जाता है और कच्चे माल का उपयोग राजस्थान राज्य में कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। डीईपीबी की खरीद पर आईटीसी का दावा चालान में विक्रेता द्वारा लगाए गए वैट के आधार पर है। अपीलार्थी-करदाता के अधिवक्ता ने आगे कहा कि ऐसे डीईपीबी स्क्रिप्स की खरीद पर भुगतान किए गए वैट को अंतिम उत्पादों के निर्माण में आगे उपयोग के लिए खरीदे गए सामानों पर भुगतान किया गया

इनपुट टैक्स माना जाएगा, इसलिए, यह आरवीएटी अधिनियम की धारा 18 की शर्तों को पूरा करता है और अपीलार्थी-निर्धारिती इन डीईपीबी/इयूटी फ्री लाइसेंस/इयूटी क्रेडिट स्क्रिप पर आईटीसी के लिए पात्र है। अपनी दलीलों के समर्थन में, अपीलार्थी-करदाता के अधिवक्ता ने जे.के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम बिक्री-कर अधिकारी, कानपुर और अन्य एआईआर 1965 एससी 1310 में रिपोर्टित; विकास सेल्स कार्पोरेशन और अन्य बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त और अन्य, एआईआर 1996 एससी 2082 में रिपोर्टित; यशा ओवरसीज और अन्य बनाम बिक्री-कर आयुक्त और अन्य (2008) 8 एससीसी 681 में रिपोर्टित उच्चतम अदालत के निर्णयों; वाणिज्यिक अभियंता और बॉडी बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड बनाम संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय और अन्य के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आईएलआर (2015) एमपी 2668 में रिपोर्टित निर्णय; और जागृति प्लास्टिक्स लिमिटेड और अन्य बनाम व्यापार और कर आयुक्त (2015) 223 डीएलटी 571 में रिपोर्टित मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा किया है।

5. राजस्व के लिए विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि आरवीएटी अधिनियम की धारा 18 की योजना के अनुसार, आईटीसी को केवल उन मामलों में अनुमति दी जाती है जो उप-धारा (1) के खंड (क) से (छ) के तहत गणना की गई है। चूंकि विचाराधीन वस्तुओं, अर्थात् डीईपीबी/इयूटी फ्री लाइसेंस/इयूटी क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग मशीनरी/कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क के भुगतान के विरुद्ध किया गया है, जो आरवीएटी अधिनियम की धारा 18 (1) के किसी भी खंड के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए आईटीसी को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था। अपनी दलीलों के समर्थन में, राजस्व के अधिवक्ता ने शा कांतिलाल जयंतिलाल बनाम तमिलनाडु सरकार (2017) 97 वीएसटी 295 (मद्रास) में रिपोर्टित मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा किया है। राजस्व के अधिवक्ता ने जयम एंड कंपनी बनाम सहायक आयुक्त और अन्य (2016) 15 एससीसी 125 में रिपोर्टित उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है जिसमें कहा गया कि डीलर को आईटीसी के लाभ का दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है क्योंकि यह एक कानून के आधार पर दी गई रियायत है और जब भी किसी कानून या अधिसूचना द्वारा रियायत दी जाती है, तो रियायत का लाभ उठाने के लिए उसकी उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन करना

आवश्यक है। राजस्व के अधिवक्ता ने आगे कहा कि जागृति प्लास्टिक्स (सुप्रा) और कमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के निर्णय, जिन पर अपीलार्थी-करदाता ने भरोसा किया है, दिल्ली वैट अधिनियम और मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के शासन के तहत हैं और आरवीएटी अधिनियम में आईटीसी के प्रावधान सही नहीं हैं और इसलिए इन निर्णयों का वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

6. दोनों पक्षों द्वारा दी गई दलीलों को सुना, एसटीआर के रिकॉर्ड को स्कैन किया और बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार किया।

7. इस मामले में, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या राज्य के भीतर डीईपीबी/इयूटी फ्री लाइसेंस/इयूटी क्रेडिट स्क्रिप पर वैट का भुगतान करने के बाद इसकी खरीद, क्या कोई डीलर इस तरह से भुगतान किए गए वैट पर आईटीसी का दावा कर सकता है, यदि संबंधित माल का उपयोग कच्चे माल के आयात पर देय सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जाता है।

8. चूंकि इसमें शामिल मुद्दा आरवीएटी अधिनियम के तहत आईटीसी की पात्रता से संबंधित है, इसलिए आरवीएटी अधिनियम की धारा 18 के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" धारा 18- इनपुट टैक्स क्रेडिट

(1) उप-धारा द्वारा कवर किए गए डीलरों के अलावा पंजीकृत डीलरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी

(2) धारा 3 या धारा 5 के तहत किसी पंजीकृत डीलर से राज्य के भीतर किए गए किसी भी कर योग्य सामान की खरीद के संबंध में उस सीमा तक और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, निम्नलिखित के प्रयोजन के लिए हैं:-

(क) राजस्थान राज्य के भीतर बिक्री; अथवा

(ख) अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री; अथवा

(ग) भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री; अथवा

(घ) बिक्री के लिए छूट प्राप्त वस्तुओं के अलावा माल की पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग किया जा रहा है; अथवा

(ड) कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा रहा है, सिवाय उन वस्तुओं को छोड़कर जो राज्य सरकार द्वारा छूट प्राप्त वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के निर्माण में, राज्य के भीतर या अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के लिए अधिसूचित की जा सकती हैं; अथवा

(च) भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री के लिए माल के निर्माण में माल की पैकिंग सामग्री के रूप में या कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा रहा है; अथवा

(छ) छूट प्राप्त वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के निर्माण में पंजीगत वस्तुओं के रूप में राज्य में उपयोग किया जा रहा है;

हालांकि, यदि खरीदे गए माल का उपयोग आंशिक रूप से इस उप-धारा में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए और आंशिक रूप से अन्यथा के रूप में किया जाता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को इस उप-धारा में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सीमा के अनुपात में अनुमति दी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति केवल विक्रेता द्वारा देय कर जमा के सत्यापन के बाद ही दी जाएगी, जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

...

(जोर दिया गया)"

9. यह स्थापित और निर्विवाद है कि डीईपीबी/इयूटी फ्री लाइसेंस/इयूटी क्रेडिट स्क्रिप आरवीएटी अधिनियम के प्रयोजन के लिए 'सामान' हैं। विकास सेल्स कारपोरेशन (सुप्रा) और यशा ओवरसीज एंड ओर्स (सुप्रा) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी स्थिति का निपटान कर दिया गया है।

10. यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि अपीलार्थी-निर्धारिती, एक पंजीकृत व्यापारी, ने वैट के भुगतान के बाद किसी अन्य पंजीकृत डीलर से सामान खरीदा था। इसलिए, अपीलार्थी-करदाता ने आरवीएटी अधिनियम की धारा 18 (1) में उल्लिखित पहली शर्त को पूरा किया है। विचाराधीन वस्तुओं को तब कच्चे माल के आयात के लिए उपयोग किया जाता था। वर्तमान मामले में विवाद की जड़ आरवीएटी अधिनियम की धारा 18 (1) में उल्लिखित

दूसरी शर्त है, जो विभिन्न उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिसके तहत डीलर आईटीसी का दावा कर सकता है। अपीलार्थी-करदाता को आईटीसी का लाभ उठाने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि राजस्व के अनुसार, अपीलार्थी-करदाता का मामला आरवीएटी अधिनियम की धारा 18 (1) के किसी भी उप-खंड के तहत नहीं आता है। धारा 18 को समझने और व्याख्या करने के लिए, आरवीएटी अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों का भी विश्लेषण किया जाना आवश्यक है:

"धारा 2 - परिभाषाएँ"

(15) "माल" से सभी प्रकार की चल संपत्ति अभिप्रेत है, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त, समाचार पत्रों, धन, कार्रवाई योग्य दावों, स्टॉक, शेयरों और प्रतिभूतियों के अलावा, और इसमें कार्य अनुबंध के निष्पादन में किसी भी रूप में उपयोग की जाने वाली सामग्री, वस्तुएं और वस्तुएं शामिल हैं, पशुधन और भूमि से जुड़ी या बनाने वाली अन्य सभी चीजें जिन्हें बिक्री से पहले या बिक्री के अनुबंध के तहत अलग करने के लिए सहमति दी गई है;

(17) "इनपुट टैक्स" का अर्थ है पंजीकृत डीलर से किए गए किसी भी सामान की खरीद पर व्यवसाय के दौरान एक पंजीकृत डीलर द्वारा भुगतान किया गया या देय कर;

(28) "खरीद मूल्य" का अर्थ है किसी डीलर द्वारा भुगतान की गई या देय राशि जो सभी सहायक और आकस्मिक खर्चों और वैधानिक शुल्कों सहित वस्तुओं की खरीद के लिए मूल्यवान विचार के रूप में भुगतान की जाती है लेकिन इस अधिनियम के तहत देय कर को छोड़कर;

(29) "कच्चे माल" का अर्थ अन्य वस्तुओं के निर्माण में एक घटक के रूप में उपयोग किए जाने वाले सामान से है और इसमें निर्माण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रसंस्करण सामग्री, उपभोग्य सामग्रियों, संरक्षक, ईंधन और स्नेहक शामिल हैं;

(35) "बिक्री" अपने सभी व्याकरणिक विविधताओं और आत्मीय अभिव्यक्तियों के साथ एक व्यक्ति द्वारा नकद, स्थगित भुगतान या अन्य

मूल्यवान विचार के लिए माल में संपत्ति का प्रत्येक हस्तांतरण है और इसमें शामिल हैं,

(i) एक अनुबंध के अनुसरण में, नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए माल में संपत्ति का हस्तांतरण;

(ii) माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल है;

(iii) किराया-खरीद या किस्तों द्वारा भुगतान की अन्य प्रणाली पर माल की कोई डिलीवरी;

(iv) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए किसी भी उद्देश्य (चाहे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या नहीं) के लिए माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण;

(v) किसी अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके सदस्य को नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए माल की आपूर्ति; और

(vi) किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य तरीके से माल, मानव उपभोग के लिए भोजन या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय पदार्थ (चाहे वह मादक हो या नहीं), जहां ऐसी आपूर्ति नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए है, और इस तरह के हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति को बिक्री माना जाएगा और "खरीद" या "खरीद" शब्द को तदनुसार माना जाएगा;

स्पष्टीकरण- इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां कोई सामान पैकिंग में बेचा जाता है, ऐसे मामले में पैकिंग सामग्री को माल के साथ बेचा गया माना जाएगा;

(36) "बिक्री मूल्य" का अर्थ है किसी भी माल की बिक्री के लिए डीलर को भुगतान की गई या देय राशि, जो व्यापार में सामान्य रूप से प्रचलित प्रथा के अनुसार किसी भी प्रकार की छूट या छूट के माध्यम से

अनुमत राशि से कम है, लेकिन इसमें किसी भी वैधानिक लेवी या डिलीवरी के समय या उससे पहले प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में डीलर द्वारा की गई किसी भी चीज के लिए प्रभारित कोई राशि इस अधिनियम के तहत लगाए गए कर को छोड़कर शामिल है।

स्पष्टीकरण I.- किराया खरीद समझौते द्वारा बिक्री के मामले में, उस तारीख को माल का प्रचलित बाजार मूल्य जिस तारीख को ऐसे समझौते के तहत खरीदार को ऐसा सामान वितरित किया जाता है, को ऐसे माल का बिक्री मूल्य माना जाएगा;

स्पष्टीकरण II.- बिक्री के समय नकद या व्यापार छूट जैसा कि चालान से स्पष्ट है, को बिक्री मूल्य से बाहर रखा जाएगा, लेकिन छूट या प्रोत्साहन या छूट या पुरस्कार और इसी तरह के किसी भी पूर्व वास्तविक अनुदान को बाहर नहीं रखा जाएगा;

स्पष्टीकरण III.- जहां एक अनुबंध की शर्तों के अनुसार, माल के परिवहन के संबंध में माल ढुलाई की लागत और अन्य खर्च डीलर द्वारा खरीदार के लिए या उसकी ओर से किए जाते हैं, माल ढुलाई की ऐसी लागत और अन्य खर्चों को बिक्री मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा, अगर चालान में अलग से शुल्क लिया जाता है।

(जोर दिया गया)

11. 'इनपुट टैक्स' शब्द को किसी भी सामान पर भुगतान किए गए कर को शामिल करने के लिए एक व्यापक अर्थ दिया गया है। 'कच्चे माल' की परिभाषा भी समावेशी है और संपूर्ण नहीं है और कोई भी वस्तु जिसका उपयोग अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, उसे 'कच्चे माल' की व्यापक परिभाषा में शामिल किया जाता है।

12. इनपुट टैक्स की अवधारणा आरवीएटी अधिनियम द्वारा पेश की गई थी क्योंकि पूर्ववर्ती राजस्थान बिक्री-कर अधिनियम, 1994 में इनपुट टैक्स का कोई प्रावधान नहीं था। कर के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए इनपुट टैक्स और उस पर क्रेडिट की अवधारणा पेश की गई थी। वैंट व्यवस्था में आईटीसी के न्यायशास्त्र पर जागृति प्लास्टिक्स लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा विस्तार से चर्चा की गई थी, जिसका प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“17. ऐसे में अगला सवाल यह उठता है कि क्या यह कहा जा सकता है कि डीईपीबी स्क्रिप्स की खरीद के समय करदाता द्वारा जिन डीईपीबी शेयरों पर इनपुट टैक्स का भुगतान पहले ही किया जा चुका था, उन्हें आयातित वस्तु की बिक्री के समय उनके द्वारा एकत्र किए गए आउटपुट टैक्स के साथ समायोजित किया जा सकता है? डीटीटी का मामला यह है कि जब तक डीईपीबी स्क्रिप्स का उपयोग आयातित वस्तुओं में नहीं किया जाता है, जिन्हें बाद में बेचा जाता है, तब तक ऐसे किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। श्री सत्यकाम के अनुसार, सीमा शुल्क के प्रभाव को कम करने के लिए नकदी के रूप में डीईपीबी शेयरों का उपयोग अधिनियम की धारा 9 (4) के प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

18. धारा 9 (4) को धारा 9 (3) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिनमें से दोनों निम्नानुसार हैं:

“9. टैक्स क्रेडिट

(3) माल की खरीद के संबंध में डीलर जिस कर क्रेडिट का हकदार है, वह इस धारा की उप-धाराओं (4), (6) और (10) में वर्णित तरीके से कम की गई कर अवधि में उत्पन्न इनपुट टैक्स की राशि होगी।

(4) जहां एक डीलर ने सामान खरीदा है और माल का उपयोग आंशिक रूप से इस धारा की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट बिक्री-करने के उद्देश्य से और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाना है, तो कर क्रेडिट की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी।

19. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आयातित वस्तुओं की कीमत में ऐसे सामानों पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क का एक तत्व होता है। सीमा शुल्क के घटक को डीईपीबी स्क्रिप्स के निर्धारिती द्वारा उपयोग की सीमा तक कम कर दिया जाता है। घटी हुई सीमा शुल्क आयातित वस्तुओं के पुनर्विक्रय मूल्य में समाहित होता है। इस प्रकार, डीईपीबी स्क्रिप्स का उपयोग आयातित वस्तुओं को बेचने वाले निर्धारिती

के उद्देश्य के लिए है। इस संदर्भ में 'उपयोग' को एक ऐसे उपयोग के रूप में देखा जाना चाहिए जो माल की कीमत को प्रभावित करता है, हालांकि इसका उपयोग माल में स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता है। आयातित वस्तुओं में वास्तविक प्रत्यक्ष मूर्त या भौतिक उपयोग के लिए 'उपयोग' शब्द की समझ को सीमित करने का कोई वारंट नहीं है।

20. इस संदर्भ में सेनवैट या एमओडीवैट क्रेडिट के साथ एक सादृश्य खींचना संभव है, जिसका उद्देश्य, वैट की तरह, माल में व्यापार के विभिन्न चरणों में कई करों के व्यापक प्रभाव को कम करना था। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री-कर और सीमा शुल्क आयुक्त, रायगढ़: 2013 (32) एसटीआर 31 (बीओएम) तथ्य यह थे कि अपीलार्थी ने कच्चे तेल और तेल कुओं से निकाली गई संबंधित प्राकृतिक गैस का आर्थिक उपयोग करने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया। इसके परिणामस्वरूप हल्के हाइड्रो कार्बन, प्राकृतिक गैस और अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों का उत्पादन हुआ। कच्चे तेल को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी, जो इसलिए एक छूट प्राप्त वस्तु थी। जहां तक ओएनजीसी ने डाउनस्ट्रीम उत्पादों का भी विनिर्माण किया है, जो कर योग्य थे, इसने सेनवैट क्रेडिट नियमों के तहत निर्यात योग्य वस्तुओं के निर्माता को दी गई सुविधा के संदर्भ में इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर के संबंध में सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया। विभाग ने यह रुख अपनाया कि सेनवैट क्रेडिट मुंबई अपतटीय के तेल क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली इनपुट सेवा से संबंधित है और चूंकि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी, इसलिए सेनवैट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था। मांग की पुष्टि के खिलाफ ओएनजीसी की अपील को स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 2 (1) के साथ-साथ नियम 3 (1) (ii) में होने वाले "इनपुट सेवा" शब्द की व्याख्या इसके अर्थ के भीतर समझने के लिए की है "एक सेवा जो निर्माता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से या अंतिम उत्पाद के निर्माण के संबंध में उपयोग की जाती है। यह देखा

गया कि विचाराधीन प्रक्रिया के बिना इयूटेबल अंतिम उत्पादों का निर्माण नहीं हो सकता है।

21. मेसर्स कमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड बनाम संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय (डब्ल्यूपी संख्या 7628/2015 में दिनांक 5 अगस्त 2015 का निर्णय) मध्य प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम (एमपीवैट अधिनियम) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एक करदाता के दावे से निपट रहा था। कुछ घटक जिन पर इनपुट टैक्स का भुगतान किया गया था, उनका उपयोग अंतिम उत्पाद, अर्थात् मोटर वाहन निकाय के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी के निर्माण के लिए किया गया था। न्यायालय को यह तय करने के लिए बुलाया गया था कि क्या करदाता एमपीवैट अधिनियम की धारा 14 के तहत इनपुट टैक्स की छूट के लिए पात्र होगा। यह माना गया था कि इनपुट टैक्स में छूट प्रदान करने में विधायिका का इरादा एमओडीवैट क्रेडिट और सेनवैट क्रेडिट के प्रावधानों के समान था। एमपीवैट अधिनियम की धारा 14 (1) (क) में कहा गया है कि "यदि एक पंजीकृत डीलर द्वारा शुल्क के भुगतान के बाद किसी अन्य पंजीकृत डीलर से खरीदे गए सामान का उपयोग खरीद पंजीकृत डीलर द्वारा किया जाता है या किसी चीज के निर्माण या प्रसंस्करण में उपभोग किया जाता है या माल के संबंध में संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और भागों के रूप में उपयोग किया जाता है, तो अंतिम उत्पाद इनपुट छूट का हकदार होगा। उच्च न्यायालय ने विभाग की इस दलील को खारिज कर दिया कि जिस सामग्री पर इनपुट टैक्स का भुगतान किया गया था, उसे स्वयं बेचा जाना चाहिए और अंतिम उत्पाद बनाने के लिए किसी भी चीज के संबंध में आगे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जो अंततः बेचा जाता है।

22. कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त पुणे-III: 2009 (15) एसटीआर 657 (बीओएम) सेनवैट क्रेडिट के संदर्भ में यह माना गया था कि विज्ञापन बिक्री संवर्धन और बाजार अनुसंधान

पर भुगतान किया गया सेवा कर शीतल पेय पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य था, खासकर जब ऐसे खर्च अंतिम उत्पाद की कीमत का हिस्सा होते हैं जिस पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया था। उक्त निर्णय के पैरा 13 में यह कहा गया था कि "व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, इनपुट स्टेज वस्तुओं और सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ आमतौर पर तब तक अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि इनपुट चरण की वस्तुओं और सेवाओं के बीच संबंध स्थापित न हो। अवधारणात्मक रूप से और साथ ही नीति का मामला, कोई भी इनपुट सेवा जो अंतिम उत्पाद के मूल्य का एक हिस्सा बनाती है, उसे सेनवैट क्रेडिट के लाभ के लिए पात्र होना चाहिए।

23. इसी तरह के अन्य निर्णयों में दीपक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सीसीई, बेलापुर: 2013 (32) एसटीआर 532 (मुंबई) और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर उपायुक्त : (2012) 56 वीएसटी 68 (उड़ीसा) शामिल हैं। बाद के निर्णय में, उड़ीसा उच्च न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा था: "क्या कोयला, फिटकरी, कास्टिक सोडा, और बिजली के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य उपभोग्य सामग्रियों को उड़ीसा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 2 (25) के तहत परिभाषित "इनपुट" के रूप में माना जाना चाहिए और कोयले की खरीद पर भुगतान किए गए कर, फिटकरी, कास्टिक सोडा और अन्य उपभोग्य सामग्रियों आदि को ओवीएटी अधिनियम की धारा 2 (27) के तहत तैयार उत्पाद, अर्थात् एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम सिल्लियों और चादरों आदि की बिक्री पर देय कर के खिलाफ इनपुट-टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा किया जा सकता है? उक्त प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा:

"यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि कर के भुगतान पर खरीदे गए और इनपुट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए विद्युत ऊर्जा के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कोयला, फिटकरी, कास्टिक

सोडा और अन्य उपभोग्य वस्तुओं आदि को सीधे तैयार उत्पादों की संरचना में जाना चाहिए, जो आवश्यक है वह यह है कि उन वस्तुओं को सीधे तैयार माल के उत्पादन के लिए विनिर्माण और प्रसंस्करण में उपयोग किया जाना चाहिए। "सीधे तैयार उत्पाद की संरचना में जाते हैं" और "तैयार उत्पादों के निर्माण या प्रसंस्करण के लिए सीधे उपयोग किए जाते हैं" अभिव्यक्तियां एक ही बात नहीं हैं। दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। पूर्व में, जबकि माल सीधे तैयार उत्पादों की संरचना में जाता है, बाद में माल सीधे तैयार उत्पादों के निर्माण/प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। इसलिए, कोयला, फिटकरी, कास्टिक सोडा और अन्य उपभोग्य वस्तुएं, आदि, जिनका उपयोग विद्युत ऊर्जा के निर्माण/उत्पादन के लिए किया जाता है, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम सिल्लियों की विनिर्माण प्रक्रिया के साथ अटूट रूप से जुड़े हुए हैं; वे इनपुट के अलावा कुछ भी नहीं हैं और इस तरह के इनपुट की खरीद पर भुगतान किया गया कर तैयार उत्पादों की बिक्री पर भुगतान किए गए/देय आउटपुट टैक्स के खिलाफ सेट ऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करेगा।

24. न्यायालय को कोई कारण नहीं दिखता कि डीवैट अधिनियम की धारा 9 (4) के साथ धारा 9 (1) के तहत प्रदान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में एक समान दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए। सीमा शुल्क के प्रभाव को कम करने के लिए इनपुट टैक्स का भुगतान करने के बाद किसी अन्य पंजीकृत डीलर से खरीदे गए डीईपीबी शेयरों के निर्धारितियों, जो पंजीकृत डीलर हैं, द्वारा उपयोग को आयातित वस्तु की बिक्री के प्रयोजनों के लिए ऐसे डीईपीबी शेयरों के उपयोग के रूप में माना जाना चाहिए। डीईपीबी के शेयरों ने बाजार में निर्धारितियों द्वारा बेची गई आयातित वस्तु के मूल्य में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है। ऐसी कई अमूर्त वस्तुएं हो सकती हैं जो अंतिम उत्पाद के मूल्य पर प्रभाव डालती हैं जैसे कि विज्ञापन लागत जिसके संबंध में इनपुट सर्विस टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है, जैसा कि कोका कोला

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में था। यह दिखाया जाना है कि इस तरह के इनपुट टैक्स भुगतान किए गए सामानों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह से अंतिम उत्पाद की बिक्री में योगदान दिया है।

25. न्यायालय ने डीटीटी की इस अन्य दलील को भी खारिज कर दिया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक कि करदाता स्वयं डीईपीबी शेयरों में काम नहीं कर रहे हों। दूसरे शब्दों में, वर्तमान मामले में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि निर्धारितियों को उसी वस्तु, अर्थात् डीईपीबी स्क्रिप्स में डीलर होना चाहिए, जिनका उपयोग आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क के भुगतान में किया गया था, जिसमें वे कारोबार कर रहे थे। इस तरह की व्याख्या मूल्य वर्धित करों की प्रणाली शुरू करने के उद्देश्य को नकार देगी, अर्थात् विभिन्न चरणों में कई करों के व्यापक प्रभाव को कम करने के लिए। जब तक यह दिखाया जाता है कि डीईपीबी स्क्रिप के उपयोग ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेचे जाने वाले उत्पाद की लागत को प्रभावित किया है, डीईपीबी स्क्रिप पर भुगतान किए गए इनपुट टैक्स के क्रेडिट से निर्धारितियों को इनकार नहीं किया जा सकता है। (जोर दिया गया)"

13. वाणिज्यिक इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय का पैरा 14 भी उल्लेखनीय है:

"14. वैट अधिनियम में निहित इनपुट टैक्स की छूट देने के लिए प्रावधान प्रदान करने में विधायिका का इरादा आबकारी कानून में लागू एमओडीवैट क्रेडिट और सेनवैट क्रेडिट के प्रावधानों के समान है और जब धारा 14 (1) (क) की उपधारा 2 और 4 इंगित करती है कि शुल्क के भुगतान के बाद किसी पंजीकृत डीलर द्वारा किसी अन्य पंजीकृत डीलर से खरीदे गए माल का उपयोग क्रय पंजीकृत डीलर द्वारा किया जाता है या किसी वस्तु के निर्माण या प्रसंस्करण में उपभोग किया जाता है या माल के संबंध में संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और भागों के रूप में उपयोग किया

जाता है अर्थात् अंतिम उत्पाद इनपुट छूट का हकदार है। यदि किसी डीलर को इनपुट छूट देने में विधायिका का यह इरादा है, तो यह विधायी उद्देश्य से परे होगा यदि विधायिका के इरादे की व्याख्या विभाग द्वारा की जाती है, यह कहते हुए कि उपयोग की गई या उपभोग की गई सामग्री बेची जानी चाहिए और अंतिम उत्पाद बनाने के लिए किसी भी चीज के संबंध में आगे उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जो अंततः बेचा जाता है। विधायिका का यह इरादा कभी नहीं हो सकता।

14. कर बोर्ड ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित जागृति प्लास्टिक्स लिमिटेड (सुप्रा) के निर्णय को निम्नलिखित तरीके से प्रतिष्ठित किया था:

“11. दिल्ली वैट अधिनियम की उपरोक्त धारा के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि एक डीलर को उसकी व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान की गई खरीद के संबंध में कर क्रेडिट उपलब्ध है और माल का उपयोग उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिक्री-करने के उद्देश्य से किया जाता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त संदर्भित निर्णय में 'उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किए जाने वाले' शब्दों का विश्लेषण किया है और डीईपीबी स्क्रिप की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी है। लेकिन आरवीएटी अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि धारा 18 में निहित है, दिल्ली वैट अधिनियम की धारा 9 के समान नहीं हैं, इसलिए, उक्त निर्णय आरवीएटी अधिनियम के तहत मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है।

14. आईटीसी की अनुमति के बारे में विभिन्न राज्यों के प्रावधानों का अवलोकन करने पर यह किसी भी संदेह से परे प्रतीत होता है कि जहां कहीं भी कोई विशेष राज्य डीईपीबी पर आईटीसी को किसी भी उपयोग के लिए अनुमति देने का इरादा रखता था, उनकी संविधियों में विशिष्ट प्रावधान किया गया था। इसलिए, यदि राज्य विधानमंडल डीईपीबी/इयूटी एंटाइटेलमेंट स्क्रिप्स, जिसका उपयोग बाद में सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जाता है, की खरीद पर इनपुट क्रेडिट की अनुमति देने का कोई इरादा होता, तो एक्सप्रेस प्रावधानों को शामिल किया जा सकता था।

लेकिन धारा 18 की भाषा आईटीसी की ऐसी कोई उपलब्धता प्रदान नहीं करती है। इसलिए, यह माना जाता है कि डीईपीबी/ड्यूटी एंटाइटेलमेंट स्क्रिप्स की खरीद पर आईटीसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब इसका उपयोग सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जाता है। ऊपर चर्चा की गई कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में, एओ ने आईटीसी को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया है और देय कर जमा न करने पर ब्याज लगाया है। इसलिए, इस मुद्दे पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है और इस मुद्दे पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

15. रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का व्यापक रूप से अध्ययन करने और दिए गए तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि अपीलार्थी-निर्धारिती का मामला आरवीएटी अधिनियम की धारा 18 (1) (ई) के अंतर्गत आता है, और इसलिए यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से कर बोर्ड द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं है:

15.1) क्योंकि अपीलार्थी-निर्धारिती ने वैट के भुगतान के बाद एक पंजीकृत डीलर से माल खरीदा है, और कच्चे माल के आयात के खिलाफ इसका उपयोग किया है, जिसका उपयोग राजस्थान राज्य में अंतिम उत्पाद के निर्माण में किया गया था। विचाराधीन वस्तुएं अर्थात् डीईपीबी/ड्यूटी फ्री लाइसेंस/ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप, विस्तार द्वारा, आवश्यक रूप से कच्चे माल का हिस्सा माना जाएगा क्योंकि विचाराधीन माल की लागत कच्चे माल की लागत में अंतर्निहित होगी, जिससे 'खरीद मूल्य' और 'बिक्री मूल्य' प्रभावित होगा।

15.2) चूंकि आरवीएटी अधिनियम की धारा 18(1)(ई) में यथा निर्धारित राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से वस्तुओं का कोई विशिष्ट बहिष्करण नहीं है और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कच्चे माल की परिभाषा व्यापक और संपूर्ण है और संकीर्ण और समावेशी नहीं है।

15.3) क्योंकि कच्चे माल का हिस्सा बनने वाली वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने से न केवल आरवीएटी अधिनियम (कर के व्यापक प्रभाव से बचने और इसके परिणामस्वरूप दोहरा कराधान होता है) का उद्देश्य विफल हो जाएगा, बल्कि प्रचलित आयात-निर्यात नीति का उद्देश्य भी विफल हो जाएगा, जिसका उद्देश्य डीईपीबी पर दिए गए निर्यात प्रोत्साहन देकर निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करना है जो मूल्य वर्धन

और आकलन योग्य मूल्य को बढ़ाता है।

15.4) चूंकि विचाराधीन वस्तुओं पर भुगतान किए गए वैट का घटक अंतिम/विनिमत वस्तुओं के आकलन योग्य मूल्य का हिस्सा होता है और जब वैट का घटक अंतिम/विनिमत वस्तुओं में समाहित होता है, तो आईटीसी के लिए इसकी अनुमति है, जब तक कि इसे विशेष रूप से बाहर न रखा जाए।

15.5) क्योंकि **जयम एंड कंपनी (सुप्रा)** के उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जिस पर प्रतिवादी-राजस्व के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया था, जिसमें यह कहा गया था कि आईटीसी एक रियायत की प्रकृति में है और डीलर को कानून द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन किए बिना आईटीसी का लाभ प्राप्त करने का कोई निहित अधिकार नहीं है, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई लागू नहीं है क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलार्थी-निर्धारिती अनुपालन करने में विफल रहा है। कुछ अनिवार्य शर्तों के साथ। बल्कि, वर्तमान मामले में 'कच्चे माल' और 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' की व्याख्या शामिल है।

15.6) क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय (खंडपीठ) के **श्री कांतिलाल जयंतिलाल (सुप्रा)** के निर्णय पर प्रतिवादी-राजस्व के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया था, जिसमें तमिलनाडु वैट अधिनियम, 2006 की धारा 19 (1) के तहत डीईपीबी लाइसेंस पर डीलर को आईटीसी के लाभ से वंचित कर दिया गया था क्योंकि डीईपीबी लाइसेंस, हालांकि माल माना जाता था, तमिलनाडु वैट अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट कर योग्य वस्तुओं में अपना स्थान नहीं पाता था। वर्ष 2006 का भी वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि इस मामले में डीईपीबी लाइसेंस को कच्चे माल की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसे आरवीएटी अधिनियम की धारा 18 (1) (ई) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

15.7) यद्यपि **जागृति प्लास्टिक्स लिमिटेड (सुप्रा)** का निर्णय उन प्रावधानों पर आधारित है जो आरवीएटी अधिनियम की धारा 18 के अनुरूप नहीं हैं, तथ्य यह है कि आईटीसी के अंतर्निहित सिद्धांत/न्यायशास्त्र को बहुत विस्तार से रेखांकित किया गया है और यह न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है। आरवीएटी अधिनियम के प्रावधानों में उभरने वाले सिद्धांतों को लागू करते हुए, अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि अपीलार्थी-निर्धारिती को आरवीएटी अधिनियम की धारा 18 (1) (ई) के तहत आईटीसी के लाभ का हकदार माना जाएगा, खासकर जब इसके लिए

कोई विशिष्ट बहिष्करण नहीं है।

16. पूर्वगामी विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, ऊपर दिए गए कानून के प्रश्नों का उत्तर अपीलार्थी-निर्धारिती के पक्ष में और प्रतिवादी-राजस्व के खिलाफ दिया जाना है।

17. तदनुसार, इन सभी एसटीआर को अनुमति दी जाती है। कर बोर्ड और नीचे दिए गए अधिकारियों के आदेशों को रद्द किया जाता है।

18. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया माना जाए।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति

ANIL SHARMA/31-34

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी.के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।